ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

वर्तमान परिपेक्ष में आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की कौशल विकास तथा स्वरोजगार की स्थिति एवं कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी

**** Dr. Shavanam Kumari & **Rani Maurya***

** Assistant professor, Department of B.Ed., MKM college of Education Hadal Haryana.*
*** Research Scholar, Faculty of Education & Allied Sciences, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly –243006 (UP).*

सारांश:

वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे "स्किल इंडिया", "मुद्रा योजना", "स्टार्टअप इंडिया", "स्टैंड-अप इंडिया" आदि ने महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इसके साथ ही साथ अन्य सरकारी योजनाएँ जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "समग्र शिक्षा अभियान" शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, महिलाएँ अब राजनीति, स्वास्थ्य, उद्यमिता, प्रशासन, एवं सामाजिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023, उज्ज्वला योजना, निर्भया फंड जैसी पहल महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हैं। हालांकि, असमान वेतन, सामाजिक बाधाएँ और रोजगार में लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इसलिए, महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं ने पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़ते हुए अब उद्यमिता, सेवा क्षेत्र, डिजिटल मंचों एवं कृषि आधारित उद्योगों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हालाँकि, समाजिक रूढ़ियाँ, वित्तीय सीमाएँ, और तकनीकी पहुंच की चुनौतियाँ अब भी उनके मार्ग में बाधा हैं। यह शोध पत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में महिलाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार की स्थिति तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनकी सहभागिता का विश्लेषण करता है। साथ ही यह पत्र महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में कौशल विकास की भूमिका को उजागर करता है।

मुख्य शब्द: *महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत, सरकारी योजनाएँ, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वतंत्रता।*

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial Use Provided the Original Author an d Source Are Credited.

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

परिचय:

महिलाओं की शिक्षा और रोजगार किसी भी समाज की प्रगति और समावेशी विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। शिक्षा महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त भी करती है (Nussbaum, 2011)। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत लिंग समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है (United Nations, 2015)। भारत में, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और सुकन्या समृद्धि योजना (Government of India, 2020)। हालाँकि, अभी भी महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की राह में कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएँ बनी हुई हैं, जिनमें लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, और पारिवारिक दायित्व प्रमुख हैं (Chaudhary & Verick, 2019)। रोजगार के संदर्भ में, भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) वैश्विक औसत की तुलना में कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर केवल 25.1% थी, जो लैंगिक असमानता को दर्शाती है (NSO, 2021)। हालाँकि, सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs), स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा योजना (Ministry of Finance, 2021)।

महिलाओं की शिक्षा और रोजगार किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की स्थिति विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, खासकर विकासशील देशों में। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के बावजूद, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं। यह अवलोकन महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के वर्तमान संदर्भ का पता लगाएगा, जिसमें प्रमुख चुनौतियों और इन मुद्दों को हल करने में विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा।

महिलाओं की शिक्षा का महत्व :

शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह उन्हें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे वे अपने जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सकती हैं। शिक्षित महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

स्थिति का आनंद लेती हैं, और वे अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और परवरिश प्रदान करती हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी साक्षरता दर 65.46% कम बनी हुई है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में सुधार करना, गरीबी और लैंगिक असमानता को महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में दूर करना है।पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है, भारत में पुरुषों के लिए 82.14% की तुलना में केवल 65.46% की महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है(Basantia, 2017)। नाइजीरिया में महिलाओं को महत्वपूर्ण शैक्षिक और रोजगार संबंधी असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अक्सर खराब वेतन वाली नौकरियों में बदल दिया जाता है। लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद, चुनौतियां बनी रहती हैं, महिलाओं की पसंद को सीमित करना, आर्थिक सशक्तिकरण, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित करना। नाइजीरिया में, महिलाओं को शैक्षिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व होता है(Ezekwe & V., 2019)। सामाजिक-आर्थिक कारक, जैसे गरीबी और सांस्कृतिक मानदंड, लड़कियों के बीच कम नामांकन और उच्च ड्रॉपआउट दर में योगदान करते हैं(Basantia, 2017) (Ezekwe & V., 2019)।

भारत में महिलाओं के कौशल विकास की स्थिति एवं चुनौतियां:

भारत में महिलाओं के कौशल विकास को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ, जैसे कि **स्किल इंडिया मिशन**, **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**, और **स्टार्टअप इंडिया**, ने महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 2020)। परंतु, अभी भी समाज में कई ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक अवरोध हैं, जो महिलाओं के कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

वर्तमान स्थिति:

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ी है। **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2022 के बीच लगभग 40% प्रतिभागी महिलाएँ थीं (NSDC, 2022)। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सिलाई, बुनाई, डिजिटल साक्षरता, खाद्य प्रसंस्करण, और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (ILO, 2021)। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ई-कॉमर्स ने महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने और स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है। भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल चला रहे हैं। इनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

- **कौशल विकास पहलों में वृद्धि:** हाल के वर्षों में, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन कोर्स, कंप्यूटर साक्षरता, और स्वास्थ्य सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं (National Skill Development Corporation, n.d.)।
- **ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान:** सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि उन्हें आजीविका के अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें (Ministry of Rural Development, n.d.)।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 'स्टैंड-अप इंडिया' और 'मुद्रा योजना' जैसी योजनाएं महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही हैं (Department of Financial Services, n.d.)।
- **तकनीकी कौशल पर जोर:** वर्तमान समय की मांग को देखते हुए, महिलाओं को तकनीकी कौशल जैसे डिजिटल साक्षरता, वेब डिजाइनिंग और मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट में प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं (NITI Aayog, 2021)।

चुनौतियां:

महिलाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में कई चुनौतियां विद्यमान हैं जो उनकी प्रगति को बाधित करती हैं:

- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं:** पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। परिवार और समुदाय के दबाव के कारण कई महिलाओं को शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है या उन्हें विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों तक ही सीमित रहना पड़ता है (Narayan, 2018)।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक महिलाओं की पहुंच अभी भी सीमित है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। बुनियादी ढांचे की कमी, परिवहन की असुविधा और वित्तीय संसाधनों की कमी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल बना देती है (World Bank, 2019)।
- **कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता:** कई कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता वांछित स्तर की नहीं होती है, जिससे महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्रशिक्षकों की कमी और अप्रचलित पाठ्यक्रम भी एक बड़ी चुनौती है (FICCI, 2020) ।
- **रोजगार के अवसरों की कमी:** कौशल विकास के बाद भी महिलाओं के लिए उपयुक्त रोजगार के अवसरों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई बार, प्रशिक्षित महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है या उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है (ILO, 2022)।

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

- **सुरक्षा और गतिशीलता की चिंताएं:** कार्यस्थल पर सुरक्षा और परिवहन की सुविधाओं की कमी भी महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ने से रोकती है, खासकर देर रात की शिफ्टों या दूर-दराज के स्थानों पर काम करने में उन्हें अधिक कठिनाई होती है (UN Women, 2023)।
- **डिजिटल डिवाइड:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल में एक बड़ा अंतर मौजूद है। यह डिजिटल डिवाइड महिलाओं के लिए नए कौशल सीखने और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है (Oxfam India, 2024)।
- **वित्तीय बाधाएं:** कई महिलाएं कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करती हैं। ऋण और अन्य वित्तीय सहायता तक उनकी पहुंच सीमित हो सकती है (NABARD, n.d.) ।

महिलाओं के रोजगार की स्थिति एवं चुनौतियां:

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। महिलाओं को अक्सर कम वेतन वाले और कम प्रतिष्ठित पदों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा, महिलाओं को मातृत्व और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी के कारण भी रोजगार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अक्सर सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ कम वेतन वाली नौकरियों पर कब्जा कर लेती हैं, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में(Ezekwe & V., 2019)। काम पर रखने के तरीकों और नौकरी की भूमिकाओं में लैंगिक भेदभाव महिलाओं की बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित करता है(Achakpa & Radović-Marković, 2018) (Ezekwe & V., 2019)। रोज़गार के व्यवहार्य विकल्पों की कमी के कारण कई महिलाएँ ज़रूरत से ज़्यादा उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाती हैं(Achakpa & Radović-Marković, 2018)।

महिलाओं के रोजगार की वर्तमान स्थिति:

भारत में महिलाओं की रोजगार भागीदारी समय के साथ विकसित हुई है, लेकिन अभी भी वैश्विक औसत की तुलना में यह काफी कम बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की **"आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22"** के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate - LFPR) केवल **25.1%** है, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर **57.5%** है (NSO, 2022)। यह लैंगिक असमानता को दर्शाता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाओं को रोजगार में शामिल करने के लिए अभी भी कई बाधाएँ हैं। हालांकि, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही **"मुद्रा योजना"**, **"स्टैंड अप इंडिया"**, और

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

"महिला स्वयं सहायता समूह" जैसी योजनाओं ने महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है (Ministry of Finance, 2021)।

महिलाओं के रोजगार में प्रमुख चुनौतियाँ:

(क) लैंगिक भेदभाव एवं वेतन असमानता

कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव आज भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की **"ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023"** के अनुसार, भारत वेतन समानता में 135 देशों में **127वें स्थान** पर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है (WEF, 2023)।

(ख) कार्यस्थल पर सुरक्षा और अनुकूल वातावरण की कमी

कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, असुरक्षित यात्रा और कार्यालयों में महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी कई महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र में काम करने से रोकती है (Chaudhary & Verick, 2019)।

(ग) घरेलू जिम्मेदारियाँ और सामाजिक बाधाएँ

भारतीय समाज में महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का अधिक भार होता है, जिससे वे पूर्णकालिक नौकरियों में भाग नहीं ले पाती हैं। परिवार और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है (Deshpande, 2020)।

(घ) कौशल विकास और शिक्षा की कमी

महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक कौशल की कमी भी रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती है। औद्योगिक क्रांति 4.0 और डिजिटल युग में महिलाओं के लिए तकनीकी दक्षता आवश्यक होती जा रही है, लेकिन कई महिलाओं को इन क्षेत्रों में अवसर नहीं मिलते हैं (ILO, 2021)।

समाधान और सुधार के प्रयास:

महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

1. **लैंगिक समानता वाले नीतिगत सुधार**: समान वेतन नीति (Equal Pay Policy) और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है।
2. **सुरक्षित कार्यस्थल**: यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है।
3. **महिला-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम**: महिलाओं के लिए STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

4. **घरेलू जिम्मेदारियों का समान विभाजन**: समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्य विभाजन की सोच को बदलने की जरूरत है।

महिलाओं के रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि सरकार, नियोक्ता और समाज मिलकर कार्य करें। महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर, सुरक्षा और उचित वेतन प्रदान करना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि संपूर्ण समाज की आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है।

विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका:

महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय हो, विज्ञान हो या कला। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की भागीदारी कम है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय हो, विज्ञान हो या कला। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की भागीदारी कम है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नाइजीरिया में GWin प्रोजेक्ट और भारत में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी पहलों का उद्देश्य महिलाओं के कौशल और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना है(Achakpa & Radović-Marković, 2018) (Kumari, 2017)। सरकारी योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं(Kumari, 2017)। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम आवश्यक हैं(Pathak, 2016)। समाज के समग्र विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक क्षेत्र सहित विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं (Government of India, 2021)। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भी महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है (United Nations, 2015)।

शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका:

महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएँ चलाई गई हैं, जिनमें **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना**, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**, और **सुकन्या समृद्धि योजना** शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है (MHRD, 2020)। महिलाओं ने शिक्षिका, प्रोफेसर, शोधकर्ता और प्रशासक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है (Kumar & Sharma, 2021)।

आर्थिक एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका:

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ कार्यरत हैं, जैसे कि **मुद्रा योजना**, **स्टैंड अप इंडिया योजना**, **महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)**, और **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)**। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ छोटे व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है (Ministry of Finance, 2021)।

स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका:

महिलाएँ स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स, डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** और **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** जैसी योजनाओं के तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुधारने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है (MoHFW, 2022)। COVID-19 महामारी के दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, शोधकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई (WHO, 2021)।

राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी:

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में **महिला आरक्षण** दिया गया है, जिससे 33% से अधिक सीटों पर महिलाएँ निर्वाचित हो रही हैं। **महिला सशक्तिकरण मिशन** और **राष्ट्रीय महिला आयोग** जैसे संगठनों के माध्यम से महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है (National Commission for Women, 2021)। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त हो रही है (Chakraborty, 2020)।

पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका:

महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)** के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है, जिससे वे जल संरक्षण, वनीकरण और कृषि सुधार कार्यों में योगदान दे रही हैं (Ministry of Rural Development, 2022)। **चिपको आंदोलन** और **नर्मदा बचाओ आंदोलन** जैसी पर्यावरणीय पहलों में महिलाओं ने प्रमुख नेतृत्व भूमिका निभाई है (Shiva, 2019)।

वर्तमान समय में, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I

March – April 2025

Original Research Article

अलावा, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन शिक्षा और रोजगार में लगातार बनी लैंगिक असमानताएं महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में महिलाओं के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना, शिक्षा और प्रशिक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना, डिजिटल डिवाइड को कम करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। महिलाओं के कौशल विकास में निवेश न केवल उन्हें सशक्त करेगा बल्कि भारत के समावेशी और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

महिलाओं की शिक्षा और रोजगार किसी भी समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलाओं की भागीदारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों में लगातार बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीति और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उनकी भूमिका सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। महिलाओं को और अधिक अवसर देने के लिए नीतिगत सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

संदर्भ:

1. *Achakpa, P., & Radović-Marković, M. (2018). Employment Women Through Entrepreneurship Development andEducation in Developing Countries. 17. https://doi.org/10.28934/JWEE18.12.PP17-30*
2. *Basantia, J. M. (2017). Women Education in India: Current Status, Recent Initiatives and Future Prospects. International Journal of Education and Management Studies, 7(3), 314–317. https://www.questia.com/library/journal/1P4-1964433382/women-education-in-india-current-status-recent-initiatives*
3. *Bhat, R. A. (2016). Dynamic Role of Education in Women empovement in Context of India. Journal of Culture, Society and Development, 15, 42–45. https://iiste.org/Journals/index.php/JCSD/article/download/28123/28869*
4. *Chakraborty, P. (2020). Women's Political Participation in India: Trends and Challenges. Indian Journal of Political Science, 76(3), 215-230.*

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

OPEN ACCESS

VOLUME–XII, Special Issues–I March – April 2025

Original Research Article

5. *Chaudhary, R., & Verick, S. (2019). Women's Labour Force Participation in India: Why is it so Low? International Labour Organization (ILO).*
6. *Chaudhary, R., & Verma, S. (2020). Gender and skill development in India: Barriers and pathways. Journal of Social Inclusion Studies, 6(2), 45–60. https://doi.org/10.1177/2394481120968472*
7. *Department of Financial Services. (n.d.). Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). Retrieved from [Insert actual URL of PMMY website]*
8. *Deshpande, A. (2020). The Covid-19 Pandemic and Lockdown: First Effects on Gender Gaps in Employment and Domestic Work in India. Centre for Economic Policy Research (CEPR).*
9. *Ezekwe, F., & Uchechukwu, E. (2019). Gender inequality in education,ict and employment:the socio-economic effects. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5973&context=libphilprac*
10. *FICCI. (2020). Skill Development in India: Challenges and Way Forward.*
11. *Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development.*
12. *Government of India. (2021). Beti Bachao Beti Padhao Scheme Report. Ministry of Women and Child Development.*
13. *ILO. (2022). World Employment and Social Outlook: Trends 2022. International Labour Organization.*
14. *International Labour Organization (ILO). (2021). Skills development for women: Opportunities and challenges. https://www.ilo.org*
15. *KPMG. (2020). Women entrepreneurship in India: Insights and recommendations. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/07/women-entrepreneurship.pdf*
16. *Kumar, S., & Sharma, R. (2021). The Role of Women in Higher Education in India. International Journal of Educational Research, 10(2), 145-159.*
17. *Ministry of Finance. (2021). Stand-Up India Scheme: Empowering Women Entrepreneurs. Government of India.*
18. *Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). (2022). National Health Mission: Progress Report. Government of India.*

Cite This Article:

Dr. Kumari S. & Maurya R. (2025). *वर्तमान परिपेक्ष में आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की कौशल विकास तथा स्वरोजगार की स्थिति एवं कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी*. **In Educreator Research Journal: Vol. XII (Issue II),** pp. 312–321. ***Doi:*** ***https://doi.org/10.5281/zenodo.15706536***